

[श्री रामसेवक यादव]

बे तब क्या उन से नागा विद्रोहियों के पाकिस्तान में जाने और रेलगाड़ी लूटने और इस तरह की कार्यावाहियों के बारे में कोई बातचीत हुई थी यदि हुई थी तो उस की प्रतिक्रिया क्या थी ? उस प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री महोदय इस नतीजे पर पहुंची हैं कि नागा विद्रोहियों से बातचीत हो सकती है और देश के संविधान के अन्तर्गत ही इस समस्या का समाधान हो जायेगा ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : कोशिश तो उसी की हो रही है ।

श्री रामसेवक यादव : और जो पहला प्रश्न है ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझ से कोई बात नहीं हुई ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने साफ पूछा था कि प्रधान मंत्री जी की इन दोनों के बारे में क्या प्रतिक्रिया थी . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब दे दिया गया है । श्री ज्योतिषी ।

you may not be concerned. They have to make a statement. Shri Raj Bahadur has to make a statement.... (Interruptions.)

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी)

इस प्रश्न का उत्तर तो आने दें ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, Order.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am sorry, Sir; it is very unfortunate that you make such a statement. I would request you to refrain in future from making such brusque and brash statements. It was the Speaker who held it over but you said that you are not concerned.

Mr. Deputy-Speaker: I did not know that. Is Mr. Raj Bahadur making any statement?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): I have no statement to make. We have laid some reports of the Chanda committee on the Table of the House. I am told that Mr. Kamath put a question whether we are going to lay more reports. The main report of the committee is expected by the end of March and we shall lay a copy of that report before the House as soon as possible.

Shri Hari Vishnu Kamath: That is what is needed. Nobody said it then. Your Deputy was unable to say so.

Mr. Deputy-Speaker: Now, Mr. Jyotishi.

15.25 hrs.

RE. PAPERS LAID ON THE TABLE

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): There is another item held over—item 4 of the Order Paper.

Mr. Deputy-Speaker: I am not concerned with that item.

Shri Hari Vishnu Kamath: We are concerned; the House is concerned;

15.27 hrs.

MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—contd.

श्री उपा. प्र. ज्योतिषी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री देशमुख द्वारा प्रस्तुत किये गये कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अत्यन्त गौरव का अनुभव करता हूँ । महोदय, महामहिम राष्ट्र-

पति जी ने अपने अभिभाषण के धारम्भ में श्रद्धेय शास्त्री जी के निघन पर अपना शोक प्रकट किया । निश्चय ही शास्त्री जी इस देश की सामान्य मिट्टी से उठ कर मनुष्यता की हिमालयन ऊंचाई तक उठे । शरीर से वामन हो कर भी वे विराट थे । वे ईमानदारी, कोमलता और सरलता के जीवनमय प्रतीक थे । उन की त्याग बीरता और संकटकाल में बर्बाई गई फौलादी दृढ़ता भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी ।

महोदय, हमें खेद है कि शास्त्री जी का निघन ऐसे समय में हुआ जब कि उन्होंने शान्ति की स्थापना और युद्धों के खारमे की दिशा में एक नये मंगल पथ के निर्माण का शिलान्यास किया था । ताशकंद समझौते के इस या उस मुद्दे से इस या उस दल को कम या ज्यादा असन्तोष हो सकता है । संसार के किस समझौते से किस देश को कब पूरा संतोष हुआ है ? राजनीति का खेल ही समझौतों का खेल है । राष्ट्रीय स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए जो समझौता हमें एक मुखी और मजबूत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में दो कदम आगे बढ़ाये वह समझौता प्रादरणीय होता है ।

15.28 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTY in the Chair]

महोदय, इतिहास के ऐसे परिवर्तनकारी क्षणों में हमें अपनी बंधितक मान्यताओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठ कर देश के व्यापक हितों और विश्व की स्थितियों पर ध्यान रखते हुए विचार करना होता है । यदि यह सच है कि अन्ततः हम सब शान्ति प्रेमी हैं, हम युद्धों का आत्मा चाहते हैं, हम हर झगड़े को संगीनों की नोकों के जोर पर नहीं बरन् विवेकपूर्व बार्ता द्वारा तय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ताशकंद घोषणा हमारे प्रादर्यों की जीत का नया अध्याय है । हम सोवियत रूस के प्रधान श्री कोसीगिन के निश्चित रूप से आभारी हैं जिन्होंने एशिया खंड के दो महान् राष्ट्रों

को इकट्ठा करके एक सुदृढ़ शांतिमय विश्व के निर्माण की दिशा में एक कदम उठाया है ।

हम जानते हैं कि ताशकंद घोषणा संसार के जंगखोर देशों की छाती के लिए एक बहुत बड़ा आघात है । हम यह भी जानते हैं कि जो जंगखोर देश अपने शास्त्र बंध कर सरमाया बंटोरते हैं, वे आज भी इस बात की कोशिश करेंगे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शान्ति न हो । लेकिन हम जानते हैं कि एक ओर जहां मध्यस्थ राष्ट्र, रूस, देखेगा कि उस के धरन से उजारा गया शान्ति का दिया बाहरी हवाओं से बुझे नहीं, वहां दूसरी ओर हम यह भी आशा करते हैं कि पाकिस्तान साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथों में नहीं आयेगा । हमें आशा है कि पाकिस्तान अब तक के संघर्ष से मबक लेगा । भारत से झगड़ कर उसने अपनी जनता को कितना भूखा रखा है । इस से उम के विकास का मार्ग कितना मबरूद हुआ है । अब तक के संघर्ष ने उस को यह सिखला दिया होगा कि युद्ध उस के लिए हितकर नहीं होने वाला है । हम सब जानते हैं कि हम दोनों आइयों ने आपस में उलझ कर कितना मुकसान उठाया है । हमें विश्वास है कि अब तक पाकिस्तान यह समझ चुका होगा कि मूल के सम्झौतों से भी अपने पड़ोसी के घर में आग लगाने की कोशिश खतरनाक होती है ।

हमें भरोसा है कि प्रस्तुत घोषणा ममस्त एशिया खंड को एकता की ओर अग्रसर करेगी, जहां कहीं भी टूट है, उसे जोड़ने में सहायक होगी । हम ममस्त मानव जाति की एकता और समानता में विश्वास करते हैं । मुझे आश्चर्य है कि समानता का दुहाई देने वाले कुछ देश अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए आज भी आक्रामक नीति अपनाये हुए हैं । मैं आशा करता हूँ कि ताशकंद घोषणा उन्हें अपनी रीति-नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करेगा । विश्व की राजनीति

### [श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

को वह निश्चित रूप से एक नया मोड़ दे कर रहेगी। आकाश के तारों का ज्योतिष न जानते हुए भी पृथ्वी के ज्योतिष के अनुसार मैं यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि हम इस ताशकंद घोषणा के द्वारा एशिया में एक नये युग का आरम्भ देख रहे हैं। मुझे निश्चय है कि इस घोषणा के द्वारा दुनिया शान्ति की दिशा में अधिक शक्ति के साथ चलने को अप्रसर होगी।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तानी संघर्ष में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन जांबाज बहादुरों की प्रशंसा की, जिन्होंने अपनी वीरता द्वारा देश के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह निश्चित है कि राष्ट्रों के भवन की नींव शहीदों की हड्डियों पर खड़ी होती है। जो देश भ्रवसर आने पर रक्तदान नहीं दे सकते, उन के नाम इतिहास के पृष्ठों से मिट जाया करते हैं। हमें गौरव है इस बात का कि हम उन वर्षों की हवा में सांस ले रहे हैं, जो बलिदान के रक्त-कमल की सहस्रों पंखड़ियों की खुशबू से सुगंधित हो रहे हैं। निश्चय ही हम शान्ति और प्रेम के उपासक हैं। लेकिन शान्ति और प्रेम की उपासना कायर की उपासना नहीं है। रहस्यवादी मलिक मुहम्मद जायसी ने छः सात सौ बरस पहले कहा था : "ध्रुव तैं ऊंच प्रेम ध्रुव ऊंचा, सिर देई पांव देई सोई छूवा"। प्रेम का ध्रुव आकाश के ध्रुव तारे से भी ऊपर उगता है। जो लोग सिर काट कर उस पर पैर रख कर ऊंचे उठते हैं, वही उस ध्रुव-तारे को छू सकते हैं। देश भक्ति और राष्ट्रोत्थान का ध्रुव-तारा भी उन्नति के आकाश में उगता है। उसे वही छू सकती हैं, जो अपने सिर को जमीन में दफनाने को तत्पर रहती हैं। हमें इस बात का गौरव है कि पिछले युद्ध में हमारे देश के नीजवानों ने, हमारे देश की जनता ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वे रक्तदान में संसार की किसी कौम से पीछे नहीं हैं।

हमें खुशी है कि इस बात की कि राष्ट्रपति जी ने गुट-विमुक्त शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की हमारी नीति का पुनरुद्घोष किया है। हम जानते हैं कि दुनिया में—और हमारे देश में भी—कुछ लोग हम को इस या उस गुट में शामिल करने के लिए बार-बार झटके दिया करते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी कुछ ऐसे राजनैतिक दल हैं, जो प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप से इस या उस गुट के हामी हैं। हमें हर्ष है इस बात का कि पंडित नेहरू के विशाल दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र ने जिस निर्गुटी नीति का पुरश्चरण किया, उन के सौम्य सहयोगी शास्त्री जी के नेतृत्व में भी देश उस नीति पर चला और आज क्रान्तिदर्शिनी इन्दिरा जी के नेतृत्व में भी हमारी सरकार उस नीति पर मजबूती ब्रे भड़ी है। यह सच है कि हम हमारे साथ ईमानदार मैत्री निभाने वाले राष्ट्रों के प्रति सर्वदा आभारी हैं। ऐसे मित्रों के हम सर्वदा के लिए ईमानदार मित्र हैं। लेकिन यह भी सच है कि हम कभी भी अपनी रीति और नीति के निर्धारण में अपने विवेक और न्याय की तराजू को फेंक कर चलने को तैयार नहीं हैं। हमारी सरकार इस बात को बार-बार घोषित कर चुकी है कि हम किसी राष्ट्र की पूछ के दुमछल्ले नहीं हैं। हमें इस बात का गौरव है कि हमारी इस नीति को हमारे मित्र सोवियत रूस, युगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, कनेडा, जापान और अमरीका जैसे महान् देशों ने सराहा है।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने पुर्तगाल द्वारा अधिभूत छोटे-छोटे देशों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और रोडेशिया की जनता पर कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों पर खेद प्रकट किया। हम स्वाधीनता और प्रजातंत्र के समर्थक हैं। जहां भी कोई देश दूसरे देश पर हावी है, हमारी सहानुभूति हर जगह दलितों और क्षोभितों के प्रति है। जहां पर भी एक बेब

दूसरे देश का शोषण करता है, एक देश अपनी रियाया को पैरों तले रौंदता है, वहां हमारी सहानुभूति और हमदर्दी उन शोषितों और पददलितों के साथ है ।

हमारे नेता ने हमें सिखाया है कि हमारी आजादी विश्व की आजादी का एक अंग मात्र है । जब तक सम्पूर्ण विश्व आजाद नहीं होता है, हम अपनी आजादी को प्रधूरा समझते हैं । हमारे नेता ने हमें सिखाया है कि सारा संसार एक है और उस संसार के प्रति हम ने एकता का भाव स्थापित करना है । हमारी आजादी सारे संसार की आजादी से सम्बद्ध है । जब तक हम सारे संसार को आजाद कराने में सफल नहीं होते हैं, तब तक हमारी आजादी अधरी है ।

हमें हर्ष है कि राष्ट्रपति जी ने दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद के विरुद्ध चल रहे संघर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की । हम स्वयं अपने देश में भाषा, जाति, वर्ण और धर्म के भेदों को गहरा दफ़ना कर समानता की एक उच्च समभूमि के निर्माण में जुटे हैं । वैयक्तिक विकास की परिपूर्ण स्वाधीनता के हामी होते हुए भी हम किसी व्यक्ति, दल अथवा समाज द्वारा अन्याय व्यक्तियों, दलों अथवा समाजों के शोषण के कट्टर विरोधी हैं । हमारा पूर्ण समर्थन है उन के लिए, जो आजादी, मानव की एकता और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं । हम उन सब के भाई हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, पदमर्दित हैं । उन का संघर्ष हमारा संघर्ष है ।

हमें दुःख है कि पाकिस्तानी संघर्ष के समय ब्रिटन ने ईमानदारी के साथ हमारे न्यायपूर्ण मुद्दों पर हम को सहयोग और समर्थन नहीं दिया । कामनवेल्थ का मन्त्रिया और प्रजातंत्र का समर्थक होने के नाते हम उस से यह अपेक्षा करते थे कि वह हमारे न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करे, लेकिन

उस ने ऐसा नहीं किया । न्याय हमारे पक्ष में होते हुए भी उस ने काश्मीर के मुद्दे को उलझाया । यही नहीं, खबर है कि चीनी संघर्ष के वक्त भी उस ने चीन को शस्त्रास्त्र बेच कर संघर्ष की भाग में ईंधन डाला । हमारे देश की जनता को इस का गहरा सदमा है । हमें यह जान कर और भी खेद हुआ कि उस ने प्रजातंत्र के समर्थक, हमारे साथी, अमरीका को भी हम से पृथक् हटाने की कोशिश की और उसे गुमराह किया । आजादी के संघर्ष के दिनों में हमारे महान् नेता, राष्ट्रपिता गांधीजी, ने हमें संघर्ष करते हुए अपने विरोधी से भी प्रेम रखने का पाठ पढ़ाया था । फलतः संघर्ष के दिनों में इंग्लैंड और हमारे बीच कटुता नहीं बढ़ने पाई थी । हमें खेद है कि पिछले दो संघर्षों के दौरान ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई नीति ने हमारे और उस के बीच की मिठास को कम किया है । हम चाहेंगे कि ब्रिटेन बदलते हुए जमाने के तेवर समझे और हमारे न्यायोचित मुद्दों को समर्थन दे । वह यह बात महसूस करे कि अगर उस के भारतवर्ष के साथ मित्रता कायम रखनी है, तो उस को ईमानदारी के साथ हमारे ईमानदार मुद्दों पर भारतवर्ष का साथ देना पड़ेगा ।

हमें खेद है कि पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी अधिकांश उत्पादन-शक्ति उस दिशा में लगा देनी पड़ी थी और इसलिए तथा वर्षों की कमी के कारण हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में इस वर्ष काफ़ी कमी आई है । उपभोग्य पदार्थों की कमी के कारण मृत्यों में भी वृद्धि हुई है और अनेक प्रकार के प्राकृतिक बोगों के कारण प्रायिक उत्सर्जनों भी हमारे सामने खड़ी हुई हैं । लेकिन यह निश्चित है कि जिस प्रकार हमारे बीरों ने मोर्चों पर ज़ुलूम का बहादुरी से सामना किया, उसी प्रकार हमारी जनता इन चिन्कतों का भी बीरता से सामना कर के उन पर विजय प्राप्त करेगी..।

[श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

“भारतवासी बचत करो, मां की शोली घन से भरते”, हमारा आज का नारा है। यह सच है कि कुछ विदेशी सरकारें हमें अपने इस अर्थ-संकट में सहयोग देना चाह रही हैं। वे हमें अन्न और अन्नोत्पादन की वृद्धि के अन्यान्य उपकरण देने को तैयार हैं। हम उन सब के आभारी हैं। समस्त विश्व में एकरता और भाई-चारा कायम करने के लिए इस तरह का सहयोग आवश्यक भी है और वांछनीय भी। लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिये कि बाहरी सहायता का कम से कम उपयोग करें। विदेशी सहायता का हर कदम हमारे स्वावलम्बन के भाव को कम करता है और देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति भी पैदा करता है। हम अंदरूनी मानोपोलिस्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ बहुत कुछ चीखते और धिल्लाते रहते हैं। हमें देखना होगा और हमें ध्यान रखना होगा कि बाहरी मानो-पोलिस्ट इस देश में नये घोंसले तैयार न करने पावें। अपनी औद्योगिक और अर्थ नीति को हमें एक बार फिर तीखी नजर से देखना होगा। यह निश्चित है कि घन का कंसंट्रेशन या तो कुछ बहुत सख्त मुद्दियों में ही रहा है जिन से देश के उत्पादन में वृद्धि को बल नहीं मिल रहा है या फिर कुछ राशि ऐसे हाथों में पहुंच रही है जो उपभोग में ही उसे खर्च कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि शासन जिस गाड़ी पर सवार है, वह उसे अपेक्षित तेजी से विकास के पथ पर ले जाने में सहायक नहीं हो रही है। मैं अनुभव करता हूँ कि कुछ पुंज बहुत घिस रहे हैं। कुछ कमजोर धातु के बने हैं। कुछ जख्मत से ज्यादा आवाज कर रहे हैं। कुछ ज्यादा चीख खा रहे हैं। कुछ पहिये, मैं महसूस करता हूँ विरोधी दिशाओं में झुक रहे हैं या बेकार सिर हिला रहे हैं। पेट्रोल का कंजप्शन भी हमारी इस गाड़ी के लिए अधिक है, वह ज्यादा पेट्रोल खा रही है। सरकार को निश्चित रूप से इस ओर अधिक ध्यान देना होगा। सरकार को इस बात को देखना होगा और सख्ती से

इस पर अमल करना होगा कि जरूरत से एक पैसा भी अधिक खर्च न हो, एक पैसा भी बरबाद न हो। इस चीज को मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि शासन के कर्मचारियों को शासन की नीति पर ईमानदारी के साथ अमल करने के लिए मजबूर किया जाय। यदि हम प्रजातंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हर लेवल पर निर्धारित नीतियों पर ईमानदारी और मजबूती के साथ अमल हो।

राष्ट्रपति जी ने केरल का जिक्र करते हुए देश की खाद्यान्न समस्या पर चिंता प्रकट की है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह देखे कि एक भी आदमी भूखा न रहे। सरकार अपनी इस जिम्मेवारी से कभी भी दूर नहीं हट सकती है। हमें इस बात की शर्म आती है कि अठारह वर्ष के बाद भी हम देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना सके हैं। लेकिन यह निश्चित सत्य है कि पूर्ण जनसहयोग के बगैर कोई भी सरकार कोई भी बड़ा चीज प्राप्त नहीं कर सकती है। युगों से चली आई हमारी अर्बजानिककृषि पद्धति, कृषक की जिदगी में धनी भीषण गरीबी, प्रकृति की अलहदता और जोरों से बढ़ती आबादी को देख देश को खाद्यान्न की दृष्टि में परिपूर्ण बना देना सरल काम नहीं है। खाद्यान्न का प्रश्न किसी दल अथवा वर्ग का प्रश्न नहीं है। यह राष्ट्रव्यापी सवाल है और एक युद्ध जैसा यह सवाल है और इस को सम्पूर्ण देश के लोगों को अपने समस्त मतभेदों को भुला कर, मिल जुल कर हल करना पड़ेगा।

मैं इस मुद्दे पर स्पष्टतया कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश इस समस्या को हल करने में देश धारम्भ से ही सम्मिलित रूप से विचार कर के निर्धारित किये गए निश्चयों पर मुस्तीवी से अमल नहीं कर रहा है। एक

घोर शासन ने लैंड सीलिंग का फैसला किया। सीलिंग के प्रतिरिक्त जमीन भूमिहीनों में वितरित करने की घोषणा की। लेकिन जमींदारों के कब्जे से निकल कर सरपलस जमीन गरीब के पास न पहुंच सकी। कागज पर सीलिंग हो गया। लेकिन कहीं मेकेनाइज्ड फार्म के नाम पर तो कहीं बनावटी सहकारी खेती के नाम पर शक्तिशाली जमींदार की जमीन उसके कब्जे में बनी रही। मैं चाहूंगा कि इस का तख्तीना हमारे सामने भ्रान्त चाहिये कि जब से सरकार ने सीलिंग का फैसला किया है, तब से ले कर अब तक कितनी भूमि जमींदार के कब्जे से निकल कर गरीब किसान के पास, भूमिहीन के पास पहुंची है। मैं तो यह समझता हूँ कि शासन को यह देखना चाहिये कि उसकी जो नीति इस सम्बन्ध में रही है वह ठीक तौर से कार्यान्वित हो पाई है या नहीं हो पाई है।

कृषि के सुधार के लिये बड़ी, छोटी घोर मंशनी सिचाई योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इरिगेशन पोर्टेणियल तैयार हुआ लेकिन कहीं सिंचित क्षेत्र में मनी-क्रॉप का उत्पादन शुरू हो गया और कहीं सिचाई के दामों को चूकाने की उलझन खड़ी कर के इरिगेशन पोर्टेणियल का पूरा उपयोग नहीं किया गया। फारेन एक्सचेंज की प्राप्ति के लिए शक्कर को फैक्ट्रियां खड़ी की गईं। उन के लिए गन्ना तैयार होने लगा। कहीं तम्बाकू और मूंगफली भी होने लगी। लेकिन अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए इरीगेशन पोर्टेणियल का कदाचित ही उपयोग किया गया। कुछ ईमानदारी से अन्न पैदा करने वाले इलाकों में या तो सिचाई की योजनाओं को हाथ में ही नहीं लिया गया अथवा उन की प्रगति चींटी की रफ्तार तक ही सीमित रहा। मेरे क्षेत्र में बीना और बारना प्राजेक्ट की यही हालत हुई। कुछ अफसर नियुक्त हो गए, कागजी काम अधिक हुआ और जमीन पर कम

हुआ। छः छः वर्ष बीत जाने पर भी कोई प्रगति नहीं हुई। बीना प्राजेक्ट की चर्चा तो भैंस के आगे बजने वाली बीन की धावाज की तरह रही। नौ वर्ष में भी शासन के कण मुह्रों तक उसकी गुहार न पहुंची। शासन के कानों पर खूं तक न रेंगी। उस दिशा में क्या कदम उठाये गये, यह विचारणीय है।

होशंगाबाद जिले को सरसम्ब करने वाला तथा प्राजेक्ट कीड़े की रफ्तार से चल रहा है और नरसिंहपुर तथा जबलपुर को सरसम्ब बना कर धन धान्य से भरपूर बनाने वाले नर्मदा प्राजेक्ट की मुर्गी तो अभी घंडा ही दे रही है। मैं समझता हूँ कि बार फूटिंग पर इन प्रश्नों को तय किया जाना चाहिये था। अन्न की समस्या को सुलझाने के लिए यह बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि हमारे इंजीनियरों ने प्राजेक्टों के नाम पर शासन के धन का पूरा पूरा सदुपयोग नहीं किया है और कागजी चींटे ही ज्यादा दोड़ाये हैं।

चम्बल के बीहड़ों को रिकलेम करने की योजना पर अन्न शासन रूपया खर्च करना तो उसे मैं बहुत मूफ़ीद समझता। विदेशों से अन्न मंगाने पर जो खर्च होता है वह भी कम होता और जिन के पास भूमि नहीं है उन को भी भूमि मिल जाती। मैं चाहता हूँ कि हम अपने इन बीहड़ों पर रूपया खर्च करके इन को तोड़ें और नई जमीन तैयार कर के उस में अन्न पैदा करने की कोशिश करें। मैं इस को उचित समझता हूँ कि जमीन के एक एक चपे में खेती की जाय। एक एक चप्या जमीन जो है उस को यहाँ एक हफ्ते या पन्द्रह दिन के अन्दर गरीबों के बीच में बांट देना चाहिये या और उन्हें सहायित्व दी जानी चाहिये, बी, उन की सहायता की जानी चाहिये थी ताकि वे उस जमीन में अन्न पैदा कर सकते। इस से अन्न की जो अन्न की समस्या थी उस को हल करने में मदद मिल सकती थी।

[श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

मैं यह भी चाहता हूँ कि आज जो गाय का गोबर जला दिया जाता है, उस को जलने से बचाया जाए। हमारे देश में कोयले की इफरत है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी रेलवे ट्रैक हैं, जहाँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ वहाँ पर शासन डिपू खोले और किसानों को सस्ते दामों पर कोयला देने का प्रबन्ध करे ताकि वे अपनी रोटी उस पर पका कर गोबर को बचा सकें, और वे खाद की जगह गोबर इस्तेमाल कर सकें।

सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट की पालिसी बनाई है, जो जोज़ की पालिसी बनाई है, उस पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहता था। मैं महसूस करता हूँ कि देश में अन्न का अभाव है और इसलिए यह जरूरी हो गया है कि हमारे देश में कहीं भी यह हालत पैदा न हो जोकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में इस देश में हुई थी और कलकत्ता जैसे नगर में अन्न के अभाव के कारण हजारों आदमी भूखों मर गए थे। मैं चाहता हूँ कि शासन इधर स्थिति से देश को बचाये। शासन को मजबूर हो कर बार बार व्यापारी वर्ग को यह कहना पड़ा है कि सस्ते दामों पर गल्ला लोगों को बे दें। चूंकि अन्न की कमी है इस वास्ते शासन को मजबूर हो कर जोन बनाने की नीति अख्तियार करनी पड़ी है और साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट की नीति को अख्तियार करना पड़ा है। मुझे इस बात का दुख है कि कुछ लोग, कुछ पूंजीपति लोग मिल कर के देश को बरगला रहे हैं और कुछ किसान भी हैं जो इसी रास्ते पर चलने लग गए हैं और वे यह महसूस करने लग गए हैं कि उन से उन का गल्ला छीना जाता है। मैं इसको बहुत आवश्यक समझता हूँ कि किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिया जाए। लेकिन इस बात को भी मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि इस देश के गरीब आदमी को खाने के लिए आवश्यक मात्रा में उचित मूल्य पर अन्न उपलब्ध किया जाए।

जमाखोरी की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, जो पैसे वाले हैं, जो साधन सम्पन्न हैं वे और जो पैसा पैदा करना चाहते हैं इसको ले उन पर अंकुश लगाना चाहिये। आज किसान की भी ऐसी ही मनोवृत्ति बनती है। वह भी वही चाहता है जो बाकी चाहते हैं। मैं कहूंगा कि किसान इस तरह की बात से दूर रहें। जो गरीब हैं वे यह समझते हैं कि उन को देश के लिए श्रम करना है और वे शान्तभाव भी रखते हैं। इसी में उन का कल्याण है। जो हो, मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो जोनल सिस्टम बनाया है, वर्तमान हालत में मैं उस का हामी हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि इस को शौक से नहीं किया गया है, मगर मजबूरी में इस को अख्तियार किया गया है।

इन शब्दों के साथ युग ऋषि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है उस का मैं स्वागत करता हूँ और अख्यवाद का जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उस का मैं समर्थन करता हूँ।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 14th February, 1966."

I will now ask hon. Members to move their substitute motions, amendments.

Shri Ranga (Chittoor): I propose to move my amendments Nos. 1 and 12.

Mr. Chairman: Shri Yamuna Prasad Mandal—absent.

**Shri Sivamurthi Swamy (Koppal):** I propose to move my amendments Nos. 3, 4, 54 and 55.

**Mr. Chairman:** Shri H. N. Mukerjee, Shri Daji, Shri Ranen Sen, Shri Warrior—absent. I think I have to move them myself! Nos. 5, 6 and 7.

**Shri Khadilkar (Khed):** Is it permissible for the Chair to move amendments?

**Mr. Chairman:** No, no; the Chair is not moving.

**Shri Ranga:** Then what happens to your amendments?

**Mr. Chairman:** They fall. There is nobody to move them.

**Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad):** That is a misfortune. You can move them tomorrow.

**Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur):** I propose to move my amendments 13 to 32, both inclusive.

**Shri Pottakkatt (Tellicherry):** I propose to move my amendments 35 and 36.

**Shri Madhu Limaye (Monghyr):** I would move my amendment No. 37.

**Shri Manoharan (Madras South):** I propose to move my amendments Nos. 38, 39, 40, 41.

**Shri Kashi Ram Gupta (Alwar):** I move my amendment No. 42.

**Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki):** I propose to move my amendments Nos. 43 to 49.

**Shri Bade (Khargone):** I wanted to move my amendment No. 51.

**Dr. M. S. Aney (Nagpur):** I want to move my amendment No. 52.

**Shri Hari Vishnu Kamath:** Madam, while commiserating with you on your inability to move your own amendments, I want to move my amendment No. 58.

**Mr. Chairman:** Thank you very much.

**Shri Dinen Bhattacharya (Serampore):** I propose to move my amendments Nos. 59, 60, 61.

**Shri Mohammed Koya (Kozhikode):** Madam, I was in a committee. I may be allowed to move my amendments Nos. 9 and 10.

**Shri Ranga:** I beg to move:

(i) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address does not give any indication of an intention immediately to end the state of Emergency declared by the President and to restore the normal functioning of full democratic liberties in the country” (1).

(ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret that—

(a) the Address fails to suggest a complete reorientation of the Government's policies to deal with the serious economic situation and the distress caused by its faulty food policies and concrete measures to put agriculture on its feet so as to end the present over-dependence on imported foodgrains, such as,—

(i) abolishing of zonal and local restrictions on the sale and movement of foodgrains, gur, groundnut and all edible oils and the re-establishment of a common market throughout India;

(ii) giving the highest priority in all plans and allocations for water, credit, roads and providing incentives and facilities to farmers, through



[Shri Ranga]

- the availability of implements, diesel and kerosene oil at reasonable prices;
- (iii) putting an end to compulsory procurement and accepting the right of the farmer to sell his grain in the free market without any maximum price being imposed;
- (iv) working out a price support policy under which the Government would alongside of the traders, be an unlimited buyer of foodgrains from producers at remunerative prices to be determined according to clearly stated principles enunciated by an Agricultural Price Commission functioning as an independent statutory body; and
- (v) as a temporary measure, until production catches up with demand, supplying the poorer sections of the population with subsidised foodgrains purchased by the Government from the larger farmers at remunerative prices;
- (b) the Address fails to admit the Union Government's responsibility for the current debacle in the provision of adequate food supplies to the people of Kerala and to mention the existence of scarcity conditions in Orissa;
- (c) the Address does not show any recognition of the fact that the defence of South Vietnam and of Malaysia against aggression is in India's vital national interests nor any readiness to take the initiative in building up a system of regional cooperation and security among the countries that lie between India, Japan and Australia to meet the threat of Chinese Communist expansionism; and
- (d) the Address does not indicate any readiness to follow up the implementation of the Tashkent Agreement by building an economic basis for friendship between India and Pakistan by the abolition of tariffs and duties on goods crossing the frontier between the two countries and by setting up a Joint Committee to consider ways and means by which economic and other forms of cooperation between the two countries may be furthered to the mutual benefit of both". (12).
- Shri Sivamurthi Swamy:** I beg to move:
- (i) That at the end of the motion, the following be added, namely:—
- "but regret that in the Address no direction has been given to the Government to—
- (a) make the country self-sufficient and a welfare State by reserving at least 51 per cent. of its budget for nation building activities instead of only 19 per cent.;
- (b) provide at least 51 per cent. of its yearly budget for food and agriculture; and
- (c) increase the expenditure on productive purposes rather than on non-productive purposes". (3).
- (ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—
- "but regret that the Address has failed to call upon all Members of Parliament to rise above narrow party feelings to solve the difficult

problems of the nation as a whole by becoming:—

(a) responsible to the general voters or the people of their respective constituencies which they represent in Parliament; and

(b) united with other political and non-political parties to make the Government really a national one which could save the nation from poverty and outside aggression." (4).

(iii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address has not mentioned anything about inter-state water disputes and the appointment of a tribunal under the Inter-State Water Disputes Act, 1956 before the beginning of the Fourth Five Year Plan." (54).

(iv) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret the failure to draw up a master plan to irrigate the famine stricken areas in the country by launching upon small or big projects during the Fourth Five Year Plan". (55).

**Dr. L. M. Singhvi:** I beg to move:

(i) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address contains neither an analysis nor an appreciation of the tasks facing the nation." (13).

(ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the political, legal and strategic implications of the withdrawal of Indian armed personnel from certain Indian territories." (14).

(iii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the withdrawal of India from Indian territory is an act of cession which the Constitution does not countenance without an amendment of the Constitution itself." (15).

(iv) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to apprise the Parliament and the nation of the deterioration in the economic situation and the virtual stagnation brought about by slogan-mongering." (16).

(v) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not disclose the low ebb at which the public sector is functioning and fails to give an indication of how the Government propose to improve their working." (17).

(vi) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address contains no reference to the plan of the Government to bring about extensive and radical administrative reforms to lift the country from stagnation and cynicism." (18).

(vii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain a blueprint for streamlining agricultural production and for providing substantial incentives." (19).

(viii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not deal with the gigantic proportions of the runaway inflation with which the country is afflicted." (20).

(ix) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain any reference to

[Dr. L. M. Singhvi]

the need for administrative reforms and for eradication of corruption in administration." (21).

(x) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not concern itself with the sharp decline in the growth rate of our economy." (22).

(xi) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address contains no assurance of emancipating planning from orthodox ideological and dogmatic considerations." (23).

(xii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address contains no assurance of reorienting our educational system to subserve more adequately the needs of the nation." (24).

(xiii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain an assurance regarding the establishment of a Desert Development Authority." (25).

(xiv) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not spell out the Government's policy regarding the establishment of an Ombudsman-type institution in India." (26).

(xv) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not contain any reference to the lifting of emergency which seems to have no ground for its continuance." (27).

(xvi) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not include any statement of policy regarding dearness allowances and particularly regarding adequate dearness allowances for lower, middle and upper middle classes of employees." (28).

(xvii) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not contain an assessment of the magnitude of the Chinese threat." (29).

(xviii) That at the end of the motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not spell out the Government's stand on manufacture of nuclear weapons in view of the failure to check proliferation and particularly in view of the fact that Pakistan and China are making great strides in the field." (30).

(xix) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not refer to increasing unemployment and under-employment in the country." (31).

(xx) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not contain any reference to the grave foreign exchange crises confronting the country and the increasing idleness in installed capacity." (32).

**Shri Pottakkatt:** I beg to move:

(i) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address of any

suitable and immediate steps to meet the alarming food situation in Kerala State." (35).

(ii) That at the end of the motion, the following be added namely:—

"but regret that no steps have been taken against the Police excesses that have taken place in various parts of Kerala State during the recent food agitation." (36).

**Shri Madhu Limaye:** I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that mention has not been made in the Address of the following:

- (a) free and adequate supply of water to poor farmers for irrigation purposes;
- (b) suggestion to State Governments to abolish land revenue in respect of unremunerative farming;
- (c) policy to bring about a balance between the prices of finished products, cash-crops and the prices of food-grains;
- (d) ban on giving licences to close relatives of Ministers and Secretaries in order to wipe out corruption, acceptance of jobs in private companies by Government officials and the appointment of Judges to other posts;
- (e) ending the state of Emergency and releasing all detenus held under D.I.R.;
- (f) provision for immediate elections in Orissa; and Kerala; and
- (g) intention to fulfil the promise, in regard to Haji Pir, Tithwal, Kargil, Uri-Poonch." (37).

**Shri Manoharan:** I beg to move:

(i) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address no mention has been made of the desirability of ending the state of Emergency and the DIR to create a healthy atmosphere for proper functioning of democracy in the country." (38).

(ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address no mention has been made of the failure of the Government to tackle the food situation especially in Kerala." (39).

(iii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address no mention has been made of the failure of the Government in not implementing in statutory form Pandit Nehru's assurance to the non-Hindi speaking people and not according equal status to all the national languages of the country." (40).

(iv) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address no mention has been made of any concrete steps to eliminate corruption and to control rising prices." (41).

**Shri Kashi Ram Gupta:** I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address no mention has been made of—

- (a) scarcity of food materials in several parts of the country resulting in famine conditions, violence, and lawlessness;

[Shri Kashi Ram Gupta.]

- (b) any scheme of the Government of India to take immediate steps to provide famine relief in such parts of the country which have really been hard hit on account of failure of Kharif crop;
- (c) soaring prices of essential commodities and absence of any scheme of Government to compensate proportionately in the shape of D.A. to Government employees;
- (d) growing corruption in every walk of life particularly in the fair and equitable distribution of daily necessities to common folk;
- (e) continuance of zonal restrictions in the movement of food grains which is a challenge to national integrity;
- (f) appointment of a large number of Cabinet, State and Deputy Ministers from amongst the members of Rajya Sabha which is an open challenge to cardinal principles of democratic set up in the country based on adult franchise;
- (g) failure to implement the mandatory provision of Constitution regarding free education to the children up to the age limit as prescribed; and
- (h) lack of proper measures in tackling the problems of weaker sections of the population including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Adivasis and hill area people." (42).

**Shri Ram Sewak Yadav:** I beg to move:

(1) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of increasing

disparity and poverty and any programme to bring about equality and eradication of poverty among people." (43).

(ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of the ever-increasing dearness and critical situation arising therefrom and any proposal or programme to counter it" (44).

(iii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of increasing lawlessness, corruption, favouritism, bribery and any proposal to eradicate the same." (45).

(iv) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of the misuse of D.I.R., and steps to abrogate it." (46).

(v) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Government had gone back on the assurance given by the late Prime Minister to Lok Sabha and the country regarding not withdrawing from Haji-Peer, Kargil, Uri and Poonch in any circumstances and has failed to establish lasting peace between India and Pakistan, by the formation of Indo-Pak confederation or the merger of the two countries." (47).

(vi) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure to replace English by Indian languages according to the provisions of the Constitution." (48).

(vii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret that there is no mention in the Address of the failure to stop dispensation of education in two different ways—viz. through public schools and ordinary schools resulting in the failure to bring uniformity in education of all citizens in the country.” (49).

**Shri Ramchandra Vithal Bade:** I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret—

- (a) that in the Address there is no concrete programme chalked out as to ways and means of making country strong and vigilant against the Chinese menace;
- (b) that the Address fails to mention the solemn pledge taken by Parliament to drive out the Chinese aggression from our sacred soil;
- (c) that in the Address no mention has been made of the economic crisis due to the shortage of foreign exchange;
- (d) that the Address fails to mention the anti-national activities carried by hostile Nagas and the failure of the peace mission to establish law and order in Nagaland;
- (e) that the Address has not laid sufficient stress on the failure of Government to supply sufficient foodgrain in famine stricken areas such as Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat etc.;
- (f) that in the Address no reference has been made about the manufacture of atomic bomb especially when China has already prepared the same;

- (g) that the Address fails to mention the deplorable condition of refugees in Jammu & Dandakaranya;
- (h) that the Address has made no declaration that compulsory military training will be given in all Higher Secondary Schools and Colleges and to all young men, women above the age of eighteen;
- (i) that in the Address no reference has been made about the failure of Government to bring self-sufficiency in foodgrain;
- (j) no reference has been made in the Address regarding the failure of Government to supply adequate quantity of fertilisers and seeds and pesticides;
- (k) in the Address no mention has been made about the failure of Government to give cultivable waste land in Tribal areas to Adivasis and monetary aid and implements to grow more food;
- (l) the Address fails to mention the failure of the Government to take effective steps to remove indebtedness and illiteracy among agriculturists in tribal areas and to give more aid to the States which are thickly populated by Adivasis;
- (m) that the Address has not mentioned the increase in prices and consequently the price index and thus steps to increase the salary of the Government employees;
- (n) that the Address has not mentioned as to how the gap between lowest and highest income be brought down so that it may not be more than in the ratio of 1 to 10; and
- (o) that in the Address while mentioning the Tashkent

[Shri Ram Chandra Vithal Bade.]

Agreement it has not been mentioned that the Government has miserably failed in diplomacy and ceded that portion of Kashmir which legitimately belonged to India and which was conquered by our brave Jawans and thus by agreeing to withdraw our forces from Haji Pir pass, Tithwal and Kargil without taking guarantee from Pakistan not to send infiltrators in future and to call back the infiltrators already sent, the Government has failed to keep up solemn assurances given to Parliament and people." (51).

Dr. M. S. Aney: I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the discontent prevailing in certain States like Punjab, Himachal Pradesh, Vidarbha for a reconsideration of the present existence of the State of Punjab into two or three States based on linguistic, cultural, economic or other considerations as well as the position of States like Haryana in Punjab or Vidarbha in Maharashtra for separation from the existing Punjab State or Maharashtra State etc.; and has taken no notice of the Consultative Parliamentary Committee and the Cabinet Committee appointed by the Government of India to consider the demand of Punjabi Suba made by a certain section of the people of the Punjab." (52).

Shri Hari Vishnu Kamath: I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret—

- (a) that there is no clear mention in the Address of the

measures and steps, such as reduction in income disparities and provision of social security, to be taken to further the nationally accepted goal of a democratic socialist society;

- (b) the failure to check the spiralling rise in prices of essential commodities of every day use;
- (c) the failure to ensure the equitable distribution of foodgrains at controlled prices;
- (d) the failure to revoke the Proclamation of Emergency and thus restore fundamental freedoms to our people; and
- (e) that the Address make no mention of steps to mitigate the hardship caused to large masses of our people by growing unemployment and continuing retrenchment." (53).

Shri Dinen Bhattacharya: I beg to move:

(i) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain any indication about the intention of the Government to immediately revoke emergency and release all political detenus." (59).

(ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention that India will extend the Tashkent spirit to settle peacefully all border disputes with all neighbouring countries including China." (60).

(iii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the gravity of the most alarming food situation prevailing in the country due to the wrong policy pursued by the Government." (81).

**Shri Mohammed Koya:** I beg to move:

(i) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address has not taken adequate notice of the grave food situation in Kerala nor does it contain any adequate measures to relieve the situation." (9).

(ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention at all the police repression and indiscriminate arrests that are taking place in Kerala at present." (10).

**Mr. Chairman:** These amendments are before the House.

**Shri N. Dandekar (Gonda):** Madam Chairman, I have great pleasure to support the amendments that have been tabled to the President's Address by my leader, Professor Ranga. The President's Address is usually good in spots, but on this occasion there is only one spot that seems to be good, and that is the only one on which, as far as I could make out, the Mover of the motion to thank the President spent most of his time, namely, that concerned with the Tashkent Declaration. For the rest, I am unable to find in the Address anything to get enthusiastic about. I will deal with some of the main defects as I see in them and then, perhaps, if I have time, I will also deal with the Tashkent Declaration very briefly.

Madam, on the home front, in so far as political matters and developments in this country are concerned, 2465 (A1) LS—10.

I notice that a veil of complete silence has been lowered by the President over some major matters of urgent public interest and concern. Firstly, for example, there is the utterly unconstitutional continuance of the Governor's rule in Kerala. There can be no doubt whatever that, from the debate that took place on the subject in this House as well as the public notice that this matter received in the Press, there is a considerable body of opinion which, quite rightly, objects to the basically unconstitutional procedure in continuing the Governor's rule in Kerala.

Equally, Madam, another serious matter is the expressed intention of Government to be deliberately unconstitutional, as shown by the decision announced by Government at the end of the last session that they intended to continue the life of the Orissa legislature by another year. It was an extraordinary proposition which they have made, and they have done it, quite obviously, for party reasons, because it is plain to anyone who makes even a brief visit and goes round Orissa that the Government today and the legislature today in that State do not command the confidence of the public. The proper thing would have been that this year, with the completion of the full term of the State legislature, that legislature ought to go out and there ought to be fresh elections. But, as I said earlier, the Government have taken the utterly unconstitutional decision, for no reason that is justifiable except only of administrative convenience, that the life of the legislature in Orissa should be extended so as to coincide the next general elections to the State legislature with the general elections for the country as a whole.

Yet another matter of great concern in internal affairs about which the Address is completely silent is the mounting corruption in public life at high levels. There was a debate about this last year in this House. It was a debate, in general terms, about ne-



[Shri N. Dandekar]

confidence; but the House agreed that it should be a debate concerned mainly with the tremendous extent of corruption revealed in the acts and doings of Mr. Biju Patnaik and Mr. Biren Mitra at the time when they were Chief Minister and Deputy Chief Minister respectively in the State of Orissa. The House knows with what great concern this matter was approached by everybody and the notice which it received in the Press and, in particular, in Orissa which was immediately concerned with the matter. Nevertheless, one finds no mention whatever of this growing corruption. I will concede that among the last great acts which the late Prime Minister had the courage to do—in fact, on the New Year Day—was the great decision he took that there had to be certain procedural forms and certain procedural necessities for dealing with matters of corruption at high levels; and that if that was not acceptable to any high level person concerned, then that high level person was perfectly at liberty to quit.

Now, if someone should object that it is not usual to refer to matters like corruption in the President's Address, I would like to correct them, Madam, by referring to the President's Address of 1964 in which there was a reference to corruption, at that time, at administrative levels. This is what paragraph 12 of that Address said:

"To improve the tone of administration and to deal effectively and promptly with complaints of corruption, or lack of integrity, it has been decided to set up a Central Vigilance Commission which will have a status in its own sphere broadly corresponding to that of the Union Public Service Commission. Its annual reports will be placed before both Houses of Parliament."

I would have expected, Madam, a similar announcement of policy and procedure in relation to complaints

of corruption at higher ministerial levels as distinguished from corruption at administrative level. The absence of this in the Address, I consider a very serious matter in view of the developments in the course of last year.

16 hrs.

Another matter of internal politics that causes grave concern, and which has been referred to even during the few days that this session has been in progress, is the thoroughly unjustifiable continuance of the "Emergency" by Proclamation. That emergency proclamation, as everybody is aware, is supported by innumerable statutory rules called the Defence of India Rules which today pervade the entire range of human activities in this country, economic, political, law and order, every conceivable matter in this country is now being dealt with, practically wholly, under the Defence of India Rules. And everybody is equally aware that the chief characteristics of the Defence of India Rules are that they involve total suspension of all personal liberties and all freedoms and all fundamental rights, whereas in fact no emergency any longer exists in reality. There was a defence attempted about this in this House when the hon. Shri Hathi said that Government had no intention whatsoever of using these powers for political purposes. It is an assurance which no one believes and no one is prepared to accept. I gathered subsequently there was a meeting of the Home Ministers of the various States and they found that the artificial continuance of emergency and the proclamation of emergency and the Defence of India Rules were very convenient tools in their hand in order to govern the country in a lawless way. When this tool gives them so much power, I do not suppose they will ever give consideration to its abrogation. It is in the light of this that I fear that this suggestion will not receive the slightest

response and that is why I particularly feel that we on this side of the House must reiterate, in view of what I have said before, the urgent need of a review of the continuance of the vast powers under the Defence of India Rules. I would like to reiterate the appeal which we made before the general elections, namely, that six months before the next general elections all the State governments ought to go out of office, because that alone would ensure impartiality and fairness in elections. "Free and fair elections" should not be just a phrase; it should be something implemented and known to be implemented. I am asking for this assurance because so long as the state of affairs continues as I have described it and so long as these vast powers continue to be exercised by the State Governments and the Central Government, we do not expect that there will be a fair use of these powers, nor will there be free and fair elections.

**Shri Ranga:** It is a challenge to their conscience.

**Shri N. Dandekar:** I speak about this from considerable personal experience as to what constitutes free and fair elections.

Turning now to the economic aspects of the whole affair, on reading the President's Address I find the same dismal dirge, the same funeral song repeated for the last two years, not only in the President's Address, but also in the statements made by Finance Ministers, in statements made by various Ministers, that the state of the economy is continually deteriorating. It is an oft repeated story of extravagant public expenditure which must be stopped but nobody is doing anything about stopping that extravagance, of leading to merciless taxation and generous deficit financing, which again the Governments keeps on repeating must be stopped, but nothing is done about stopping it. In this connection, I was astonished

the other day when I was reading. I think about two or three weeks ago, the periodical statements issued by the Reserve Bank to find that the State Governments have an overdraft with the Reserve Bank of India of something like Rs. 100 crores.

**Shri Ranga:** Bankruptcy.

**Shri N. Dandekar:** It is, therefore, not merely the Central Government that is continuing to resort to deficit financing, both overt and covert, but also the State Governments are apparently attempting to do the same on an extensive scale. Of course, the consequences of this are again well-known, namely, an acute and continuing state of inflation reflected in steadily rising prices and ever-mounting cost of living. Again, it is a repetition of a tale year after year; the tale of bankruptcy in food and foreign exchange, of continuing mismanagement and costly failures in the public sector enterprises which yield little or no return; of deadly stagnancy in the private sector, and of steadily falling rate of growth in real terms, whether it is industrial growth or economic growth generally, or whether it is growth in the agricultural sector. The story is the same.

In other words, the chief characteristics of the President's Address, in so far as the economic front is concerned, are that it is the same story, of the same disease, of the same symptoms and of the same quack remedies and nostrums, of the same promises which are never fulfilled. Year after year, in the President's Address, in the Finance Ministers windy speeches, broadcasts and statements they keep on repeating these things ad nauseam. They go on repeating some of the remedies like cutting down non-Plan expenditure, about the need to economise on Plan expenditure, about the need for quickening up the pace of production in the public sector within the Plan expenditure, but nothing seems ever to happen. It is a story of failures

[Shri N. Dandekar]

and shortcomings of policy, not admitted, and of the need for radical changes in policy, also not admitted.

I would like to illustrate it this a few minutes by some observations on the food situation, which is an excellent example of allowing in the same muck year after year. It is a story of reviling traders and abusing the farmers, but saying nothing at all either about incompetence or profiteering by the various State Governments. It is a story of persisting in food zones with their logical corollary of smaller and smaller sealed off areas, such as districts, talukas and even groups of villages, with separate food zones of their own, and of compulsory procurement or levy in excessive quantities at unremunerative prices.

Today India is no longer one country; it is a moth-eaten fabric. It reminds me of the state of affairs with us in the years 1948 and 1949, immediately after the Indian Independence Act of 1947, when there were in this country apart from the British Provinces which we in India inherited, something like 560 Indian States. And in case Hon'ble Members are not aware of the fact, I would like to remind them that every Indian State and every Province was then a food zone and would prevent the movement of food from one area to another. That was the state of affairs right up to the end of 1949. In 1950 the country was united into one zone. All these food barriers, customs barriers and land customs, all those kinds of things that cut up the country into several bits—they were all abolished by the Constitution, when it came into force on the 26th January, 1950.

16.07 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

About the same time the compulsory procurement was also abolished, largely under the lead of Shri

Rajagopalachari, who was then the Chief Minister of Madras.

I would like to indicate very briefly the consequences of so integrating the country into one zone, in not breaking it into food districts, food talukas and food groups of villages. The consequence of such abolition of food zones and of compulsory procurement can be seen by one very simple test, namely, what was the effect on production and, therefore, what was the effect on imports. I would like to give only the figures for imports. The figure for import of foodgrains in 1951, at the commencement of the policy of abolition of compulsory procurement based on food zones and restriction on movements stood at 4.8 million tons. In 1952 it was down to 3.6 million tons. In 1953 it went down to 2 million tons, in 1954 to 0.8 million tons and in 1955 it was down to 0.7 millions. Then began our Second Five Year Plan, followed by the Third Five Year Plan. These were ten years of utter indifference and total absence of food policy, with neither a floor price policy, nor a policy of remunerative price, but just a policy of drift; merely speaking of high targets but doing nothing for effectively achieving them, talking a lot about fertilizers, but with utter neglect in establishing fertilizer plants and, in fact, taking years and years over negotiations for the establishment of fertilizer plants until it was only in 1965 that there appeared some possibility of new fertilizer plants on a giant scale being established in this country, under utilisation of irrigation potential, and neglect of small irrigation schemes, failure to supply diesel oil and electric power for irrigation purposes, neglect of seed farms. There was over this decade nothing done in fact that one would call a policy geared to the needs of the grand eloquent targets which were solemnly propounded in the two Plans.

Again, I would like to give a picture of the consequences of all this,

quite straightforwardly, on the import of foodgrains over the past ten years commencing from 1956. As I said, in 1955 the import of foodgrains was down to 0.7 million tons. Here is the subsequent story. In 1956 it was 1.4 million tons, in 1957 it was 3.6 million tons, in 1958 it was 3.3 million tons, in 1959 it was 3.9 million tons and in 1960 5.1 million tons. That covers the Second Plan. In 1961 there was a little drop in import as compared to the previous two years; it was 3.3 million tons. Then it started rising again. In 1962 it was 3.6 million tons, in 1963 it was 4.6 million tons, in 1964 it was 6.3 millions and in 1965 it was 7.5 million tons.

Now, perhaps, it will be 12, 13 or 15 million tonnes 1966;—heaven only knows what. But the conclusion that emerges here is that we need not have been in any of these years so short of foodgrains as we apparently were; we need not have had a food shortage, except in a year of particularly bad drought, of anything more than about a million or a million and a half tonnes whereas in fact we had been importing in the Second Five Year Plan at an average 3½ million tonnes per annum and in the Third Five Year Plan up to over 5 million tonnes per annum on the average.

Sir, we are going back again to the conditions of 1950 in all respects. The Government want to have food zones; they want to have districts hived off from districts; they want to have talukas and villages hived off from other talukas and villages. You cannot move rice from A to B; you cannot move wheat from B to C and so on. The whole country is one blocked economy cut up into fractions so far as movement in foodgrains is concerned.

**Shri Badi:** The collectors also are Moghul emperors.

**Shri N. Dandekar:** On the top of it, the justification is that that is the only way we could have compulsory

procurement. I would like to suggest, in the first place, that this is about the best atmosphere for a thriving industry in corruption; I cannot think of any other name for it. One thing I am certain, namely that the activity that is going to thrive in a very big way over this year, next year and so long as we continue this wretched zone system and restriction on movement, is corruption; you are going to have a vast trade in organised corruption. However, the policy of compulsory procurement will not, of course, be effectively implemented because it cannot be effectively implemented. You cannot have millions of farmers being subjected to measures of this kind, in terms of compulsory procurement and so on, and hope to get away with it.

The only right policy, I submit, would be to restore the first and primary thing, the incentive of a free market and a free market price to the farmer to produce the best that he can coupled with—and this is necessary because the agricultural economy depends so much on the vagaries of monsoon which can also play the opposite trick, namely, there could be such a good monsoon and you can have such a bumper crop that prices may collapse—remunerative floor prices which are also an essential part of a proper pricing policy. That will be the time for facilities to secure the necessary inputs. You cannot expect the agriculturist to be enthusiastic about inputs on the scale and of the type that are being envisaged in all the speeches made by the Food Minister. You cannot expect any farmer to put in inputs on the scale and of the kind involved in scientific farming—chemicals, water, irrigation, improved seeds and all that kind of thing; inputs that are going to cost a good deal—unless in the first place he is assured of the floor price and secondly, and much more importantly, he is also assured of the free market price if the free market price happens to be better than the floor

[Shri N. Dandekar]

price. Then and then only you can have interim measures for deficit areas based largely upon free movement of trade within the country supplemented by imports.

Now, Sir, I will briefly turn to the foreign affairs part of the President's Address. The hollowness of our claim to success in foreign policy, it is well known, was exposed last year, when we stood alone and friendless. Everyone, including Russia, stood non-aligned against us except for two little friends, that have always stood by us—Malaysia and Singapore. It is obvious to everybody after that situation that arose during those three or four months of conflict with Pakistan when the eyes of everybody were opened to the utter futility of the foreign policies until then followed. There was a debate in this House and it was clearly accepted that the situation demanded a reappraisal of the principles of our foreign policy and of our friends and foes. Re-orientation was indeed promised in the course of that debate. I think, Shri Chagla who spoke quite plainly and bluntly said that there was no doubt about it that the foreign policy of this country needed re-orientation as to its basic principles.

I also feel bound to say that subsequently a re-oriented policy was indeed followed by our late beloved Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, with very happy results in Burma, Ceylon and Nepal and with conspicuous success at Tashkent. I have no doubt, had destiny spared him to serve this country a little longer, he would have carried this on and re-oriented our foreign policy on the lines on which, it was agreed during the debate in this House, re-orientation was necessary.

Unfortunately, we have lost him; and we seem to be back again to the old, old chants.

I was, in fact, astonished to read this. It could have been something

written in Prime Minister Nehru's times. I find in it a remarkable exposition of the same old foreign policy that we had been following over all the years; a policy that threw us into the ditch vis-a-vis China and which threw us into another ditch vis-a-vis Pakistan. "Our Government will continue to work for peace in the world. "Om! . Shantih, shantih, shantih. "Peace is essential for our own development and progress and for the well-being of all peoples. To this end, we shall strive to strengthen international cooperation, based on the principles of peaceful co-existence, non-interference in the internal affairs of others"—and it must always be there—"non-alignment"; and so on. All this is in the President's Address. When I read this I begin wondering. I asked, are we back again to the ancient times so to speak? Apparently, we were; though I hope, we are not.

It is in the light of our experience both as to the need for changing our foreign policy principles, its basic objective and its mode of operation that I would like to examine what is stated here in relation to, for instance, our relationship with China. China is dismissed, notwithstanding the long time which the External Affairs Minister took over China, in the President's speech in three lines of two sentences; and they are masterpieces of understatement. "Unfortunately", says the President, "our relations with the People's Republic of China still continue to be strained." We just do not get on; we are just a little bit estranged. And so "The country has to be vigilant and strong." That is all of our Chinese policy. It is a remarkable exposition, a masterly understatement, as I said, of which an Englishman might well be proud, because they are supposed to be masters of understatement.

Now and again when there are official speeches about China, we have also a continued insistence on Colombo proposals as if the Colombo proposals

ever were, or ever will be, a substitute for a foreign policy *vis-a-vis* China. The Colombo proposals were, everybody knows, stillborn. They were not merely rejected, but they have been flouted by China. There is no part of the demilitarized zone which the Chinese do not occupy, if they wish to with impunity. The Chinese for their part have also committed breach of the agreement about Tibet, in regard to the autonomy of Tibet. What do we do? We say, "No; we are bound by the agreement about Tibet; all that we will do is to join in a resolution about the ill treatment of the people of Tibet."

**Shri Ranga:** That too in an apologetic manner.

**Shri N. Dandekar:** The Chinese are flouting all agreements. They have openly said so. They do not accept what they have previously agreed to about our relationship with Bhutan and Sikkim. The special position of Bhutan and Sikkim with or within the Indian Union, or the Indian Constitution or whatever you like to call it, is now rejected by China.

And what has happened to those famous Colombo powers that propounded these wonder Colombo proposals? The UAR and Ghana stand exposed as a result of the happenings of last year and the things they then said. Burma and Cambodia are of no consequence. In fact, one Member of Parliament whom I will not name, did not quite know where Cambodia was: whether in South Africa or in South America. I told him that Cambodia was in South East Asia, and he said, "Is that so?" Ceylon has a different Government now and Indonesia has no government at all. Those are the Colombo powers and those are the Colombo proposals that we keep on repeating like parrots.

What should be our policy *vis-a-vis* China? Before I answer that or attempt to do so, I think, we must take a look at South Viet-Nam, because South Viet-nam, in my judgement, is

a specific example of the Chinese Communist policy of deliberate and ruthless expansion... (*Interruption*). I have got here with me some papers which will take too long to read but which contain ample evidence to prove for instance, that Dr. Ho Chi-minh always intended to and did in fact sabotage the Geneva Agreement of 1954. We keep on harping back to this Geneva Agreement of 1954.... (*Interruption*). I do not want to quote from newspapers, but if Members who keep on interrupting me from the back would care to read the reports of the International Control Commission... (*Interruption*), there will be plenty of evidence to show that this situation in fact is one which Dr. Ho Chi-minh always intended and that he has been steadily planning for the overthrow of South Viet-nam. Since 1962, in any event in so far as India is concerned, the attitude of North Viet-nam to India is patently and absolutely clear; and it is one of continuing hostility.

Here, I will take a little time of the House to refer to certain outstanding indications of this. In 1962, this is what the Party Organ of North Viet-nam remarked:

"In opposition to China's policy for peace are the policies of the Indian authorities to seize Chinese territories by force and their attitude of obstinately rejecting China's reasonable proposition".

On July 13, 1965, last year, Hoang Van Hoan, leading a delegation of North Vietnam National Assembly said at Peking:

"While opposing imperialism, China has been holding high the banner of anti-revisionism to defend the purity of Marxism-Leninism..."

—lot of 'isms'—

"... to push forward the revolutionary struggle in Asia..."

[Shri N. Dandeker]

In reply to Ho Chi-Minh's letter of January 24 a Chinese gentleman called Liu Shao-chi who holds an important position, said:

"China and Vietnam are neighbours closely related like the lips and the teeth".

That hostility towards India, and that declared intention to swallow South Vietnam by subversive movements called "liberating movements", has been the policy of North Vietnam vis-a-vis South Vietnam.

As I said earlier, however, one has to understand this as part of the over-all Chinese policy, not just part of the North Vietnam policy. It is essential to recognise what is happening to North Korea and South Korea.....(Interruption) and the attitude as between China and Taiwan; the chinese position vis-a-vis North Vietnam and South Vietnam, Cambodia and Laos; Thagla Ridge, Bhutan and Sikkim, Bara Hoti and Ladakh—the whole thing. You have to look at the whole picture that begins somewhere in the north-east corner of Asia and ends with the north-west corner of India. It is a picture of power politics; it is a picture of China doing everything possible to establish Chinese hegemony in the whole of east and south-east Asia.

Sir, I submit what has to be recognised is that the Chinese problem is a power problem. It is not a problem of border disputes. It is not a problem of some Vietcong or any other such thing. It is a problem of power. It is a problem in which the Chinese recognise us as the only obstacle in this part of the world to their gaining complete hegemony and control over the whole of south-east Asia. I submit, in that situation, what is needed is that we must become very realistic. But we keep mouthing these phrases of non-alignment and co-existence and what not.

Let us, I say, come down to brass tacks instead. So what should we do about this? Let us work out a system of regional collective security and cooperative assistance in this part of the world, with Japan and Taiwan, with Malaysia who has stood by us all the time, with possibly Ceylon with its new Government, with Australia, with Philippines, with all those people who are frightened about China, frightened of China, knowing that we could be the only effective block in the way of the expanding Chinese power. I submit our policy must be one of approaching this problem from that angle and attempting to evolve a Chinese policy that is not concerned just with borders in the Thagla Ridge or Bara Hoti or some place in Ladakh, not just mouthing Colombo proposals and a whole lot of nonsense of that kind which became meaningless years ago.

Finally, Sir, a word about Pakistan. I regard the Tashkent Declaration as a great act of faith. I consider the Tashkent Declaration as something which, if ever possible, human beings ought to endeavour to achieve. As might be expected, it will encounter strong oppositions from the last ditchers in this country and from the obscurantists in Pakistan. I know attempts will be made to whittle down all kinds of things in it. But the main thing remains that the two countries at last did not have their heads knocked together by Mr. Kosygin as some people believed. Possibly, under the persuasive atmosphere presided over by Mr. Kosygin—one does not know what Mr. Kosygin said to them; maybe, he described the sort of picture about Chinese hegemony or whatever it is—the point to be remembered is that it is one of the greatest acts of faith in international affairs. It is not just a matter of a little clause here and a little word there. What, after all, is the difference between human beings and

animals? The difference is qualitative: that we have judgment; that we can distinguish between the good and the bad and that we are capable of committing acts of faith for the sake of human good. But I submit, acts of faith cannot thrive on barren soil nor in an environment that is hostile. If you believe in faith, if you believe in goodness, if you believe in the essential goodness of man . . .

**Shri Bade:** Pakistan does not believe in that.

**Shri N. Dandekar:** I stress it does not matter what Pakistan does or does not believe. What matters, Sir, is what you and I believe. I am not concerned with what Mr. Bhutto says or somebody else says. But what I am concerned with is that the great little man, our late Prime Minister and the greatman, President Mr. Ayub Khan—I have had also the honour of knowing him, though much less than Mr. Lal Bahadur Shastri—got together and committed an act of faith. If it comes off—I attach importance to the word 'if'; for I am not one who lives in the clouds; I am a realist—I say, if this sort of act of faith comes off, what is the future, the great future, for both India and Pakistan? I suggest, Sir, instead of carping criticisms and having obscurantist approaches and legalistic quibbles about this and that—if the Agreement is broken, it is broken; we are back where we were and everybody recognises that. But if on the other hand the Agreement is to be implemented, which is the only way in which things can move along the path that was being given to us by our late Prime Minister, it is necessary to abide by it and to commit other acts of faith, to develop trade and economic relations with Pakistan. It is, I suggest, fantastic that whereas formerly between this country and what is now Pakistan, there used to be enormous trade and traffic, all that has come to a stand-still. Is anybody going to tell me that—that is for the good of

either of these countries? I suggest what is required is further acts of faith. If a breach of faith is committed, well, we get back to where we were. But the possibility of a breach of faith is I submit no answer and is no ground for suggesting that we have no faith in the essential goodness of man. I suggest that are vast fields for mutual benefit to be explored; there are financial disputes with Pakistan; there are trade disputes with Pakistan; there are also possibilities of tremendous economic development in both countries if we got together and if we made our best attempts to get together and not keep on looking back at the past all the time.

In this connection, Sir, I would like to remind the House about the great change that has taken place in ten years in Western Europe as a result of the European Common Market. It is a fantastic change. If one were to go to Europe, if one were to read the European journals, if one were to see the economic development in Western Europe over the past decade, one would realise what an act of faith can mean. They have their difficulties. I am not going to blame anybody for those difficulties. Maybe, some may blame De Gaulle; some may blame Adenauer and others may blame Erhard. But that is not the point. The point is this that there is a lively and continual attempt to get together and to build on acts of faith which constituted the European Common Market, the Coal Community, the Steel Community and so on. There is no reason why in this great sub-continent similar acts of faith cannot be committed.

However, Sir, with this single exception—and it is a great exception—of the Tashkent Declaration that is referred to with due and just praise in the President's Address, I am sorry I find very little else to commend to this House in that Address.



**Shrimati Renu Chakravarty:** Sir, may I be permitted to move my amendments? The numbers are 5, 6, 7 and 11.

**Mr. Deputy-Speaker:** They will be treated as moved.

**Shrimati Renu Chakravarty:** I beg to move:

(i) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address fails to condemn the resumption of bombing of North Vietnam and the continued violation of the Geneva Agreement and escalation of hostilities by U.S.A. endangering world peace and particularly peace in South East Asia.” (5)

(ii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address fails to recognise the dismal failure of the food and agriculture policy of the Government leading to starvation, high prices, widespread distress whose extreme example was Kerala and dangerous dependence on imports; and also fails to spell out the necessary steps for self-sufficiency in food and the national control over the wholesale trade and distribution of food-grains.” (6)

(iii) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address fails to announce the immediate end of the State of Emergency and the release of the political detenus.” (7)

(iv) That at the end of the motion, the following be added, namely:—

“but regret that in the Address no mention has been made of—

(a) any concrete steps to raise the rice ration in Kerala State

to the satisfaction of the people there;

(b) Police repression let loose on the people especially on students in Quilon, Trichur and other districts of Kerala State;

(c) release of arrested persons and withdrawal of prosecutions in connection with the recent food agitation in Kerala;

(d) misuse of DIR to arrest and detain political workers of the Opposition Parties; and

(e) failure of the Government to take steps to hold elections and set up a popular government in Kerala.” (11)

**Mr. Deputy-Speaker:** Shrimati Renu Chakravarty.

**Shrimati Renu Chakravarty:** I wanted to speak tomorrow morning.

**Shri Warier (Trichur):** We thought, after the opening speech made by Mr. Dandekar, you would be calling somebody from the Congress Benches.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Kashi Ram Gupta.

श्री काशी राम गुप्त : भाष्य  
महोदय, देश के सामने तीन प्रमुख समस्याएँ  
है। एक जन संख्या में वृद्धि की है, दूसरी अन्न  
के उत्पादन में कमी की है और तीसरी  
देश की सुरक्षा की है। इन सब के बारे में  
हम सब अपने अपने दृष्टिकोणों से विचार  
करने हैं और कार्य करते हैं। किन्तु इस  
सब की जड़ में जो एक मूलभूत खराबी है  
उसकी तरफ सम्भवतः इस सदन के सदस्यों  
का ध्यान नहीं जाता है। वह खराबी यह है  
कि जिस प्रकार से हम अपना प्रजातंत्र चला  
रहे हैं, इस लंबड़े लूके प्रजातंत्र को चला  
रहे हैं, इस बीमार प्रजातंत्र को चला रहे हैं,  
उस में सब से बड़ा दोष किमका का है ?

मेरी समझ में वह दोष इस कांग्रेस पार्टी और इस कांग्रेस सरकार का है। साथ ही मैं यह भी समझता हूँ कि उसके बाद यह दोष हमारे विरोधी पक्ष का है। दोनों ही उस में दोषी हैं। कौन किस हद तक दोषी है यह मैं विश्लेषण करके आपको बतलाना चाहता हूँ।

आज ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार है। वह तीन सौ बहुमत से चली रही है। किन्तु हमारे देश में क्या नीति अपनाई जाती है केन्द्र में या भिन्न भिन्न प्रदेशों में, इसको आप देखें। केन्द्र की सरकार और खास तौर से प्रदेशों की सरकारें चुनाव के बाद विपक्षी दलों का राजनीतिक धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू हो जाती हैं। सत्तासङ्घ दल को शायद यह लज्जा की बात भी नहीं लगती, वह इसको पापकर्म भी नहीं समझती, उसको यह अपनी राजनीति समझती है।

**एक माननीय सदस्य :** दोनों तरफ से ऐसा होता है।

**श्री काली राम सुप्त :** जिस को यह कहने हैं कि दोनों तरफ से होता है, उसके बारे में इनको मान्य होना चाहिये कि सत्ताधारी दल के पास जो सत्ता होती है, वही उस सत्ता का दूसरे को भ्रष्ट करने का उपयोग करता है; यह हमेशा से इतिहास की बात रही है। इसलिए जो स्वयं सत्ताधारी दल होता है उसका ही इस में मुख्य दोष होता है। इसके लिए आप दूर न जा कर एक एक प्रदेश का उदाहरण ले कर देखें।

बिहार का उदाहरण आप लें। वहाँ पर एक प्रकार से एक पार्टी को खत्म करने का तरीका अपनाया गया। स्वतंत्र पार्टी को वहाँ नेल्सोनावद करने की कोशिश की गई उसको अपने अन्दर मिलाने की कोशिश की गई। उसको उन्होंने बोखा दिया।

आज इन्होंने भारतीय पार्टी का भी यही हाल किया है। इसका तरीका यह अपनाया है कि किसी को मंत्री बना दो, किसी को उपमंत्री बना दो। इस प्रकार का जाल सत्तासङ्घ दल रचता रहा है।

मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दल बहुमत में नहीं आया। चार पांच की कमी थी। अपना बहुमत बनाने के लिए जितने हथकंडे हो सकते थे अपनाये गये। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को जो विरोध पक्ष में थे उनको माथ लेने के उपाय किये गये। उसका नतीजा यह है कि उनका राजनीतिक धर्म भ्रष्ट करके इन्होंने अपना बहुमत बना लिया है।

राजस्थान को आप देखें। राजस्थान में भी पार्टी की संख्या प्रारम्भ में करीब करीब विरोध पक्ष के बराबर थी। और किसी को नहीं तो उन्होंने निर्दलीय सदस्यों को तोड़ना शुरू कर दिया। निर्दलीय शायद सन्ने होते हैं तोड़ने के लिए। उनको तोड़ कर बहुमत बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता जन संघ या स्वतंत्र पार्टी के लोगों को लुभावमान इन्होंने करने की कोशिश की। अब आखिरी दिनों में यह चक्कर चलाया है, छ महीने पहले यह चक्कर चलाया कि वहाँ के एक प्रमुख महाराजा को एम्बेसेडर बना कर विदेश में भेज दिया गया है। वह योग्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वह योग्य हैं उस में कोई शक नहीं है (इंटरव्यू)। शर्मा जी बहुत उतावलापन दिखा रहे हैं। मैं उन से प्रार्थना करता हूँ कि वह शान्ति में मेरी बात को सुनें। लेकिन यह नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक के आधार पर की गई है। आपको मान्य होगा कि एबी गदन में एक बार आदर्शीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि वे उन प्रादमियों को प्राथमिकता देने हैं एम्बेसेडर बनाने के मामले में जिन को पत्नियाँ बहुत सुन्दर होती हैं, सुटेबल होती हैं और जिन में श्री

### [श्री काशी राम गुप्त]

भी खूबियां होती हैं। उसका मतलब यह है कि वे उनके साथ रहें। आज वह स्थिति यहाँ नहीं है क्योंकि यह एक राजनीतिक चाल है। सत्ताधारी दल यह जानता है कि वह भ्रामागी चुनावों में इन बातों का उपयोग कर सकता है। जो पार्टी इस प्रकार की काम करती है, उसकी इस प्रकार की नीतियाँ देश के लिए घातक सिद्ध होती हैं, भयंकर सिद्ध हो सकती हैं।

अभी अभी आप देखें कि क्या हुआ है। प्रधान मंत्री का चुनाव सम्पन्न हुआ है। इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने दुनिया को यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि वाह यह तो सारे देश का चुनाव करना है, इस में भीफ मिनिस्टर आ गए तो क्या हुआ। मेरे साथी श्री शिवमूर्ति स्वामी कहा करते हैं कि प्रधान मंत्री का चुनाव सारे सदन को करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि जब सारे देश को प्रधान मंत्री का चुनाव करना था तो इस सदन को क्यों नहीं पूछा गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि इनका एक तरीका है काम करने का। इसी का यह फल है कि आज कोई परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे अभी ये नजर न आयें लेकिन आगे चल कर ये इतने घातक सिद्ध हो सकते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस वास्ते में कहूंगा कि स्वस्थ परम्परायें ही डाली जानी चाहिये।

दूसरी तरफ भी आप देखें। विरोधी पक्ष में भी कई दल हैं और उसमें वामपक्ष भी है। इन सभी दलों को मिला कर विरोधी दल कहा जाता है। ये दल एक दो या तीन नहीं, आठ हैं। इनके अन्दर मतभेद हैं और यह सम्भव नहीं ये सत्ता लेने की बात करें यह सम्भव नहीं हो सकता है। जब सब मिल बैठ कर बात करने की कोशिश करते हैं

और एक होने की कोशिश करते हैं तो इनके रास्ते में रोड़े अटकते हैं और अगर कोई कसर बाकी रह जाती है तो उसको कांग्रेस वाले आकर पूरा कर देते हैं। वे भी आ कर रोड़ा अटका देते हैं। इस प्रकार से इस देश में कांग्रेस को सत्ता में बनाये रखने के लिए मदद विरोधी दल वाले जाने या अनजाने में बराबर दे रहे हैं। उसका नतीजा यह होता है कि इस देश में कभी इस प्रकार की कल्पना भी नहीं होती है कि कांग्रेस के सिवा किसी दूसरे दल का राज्य भी स्थापित हो सकता है। अगले पांच वर्षों में यह स्थिति पैदा हो जाएगी कि इतिहास यह कहेगा कि इस देश के अन्दर लोगों के न चाहेते हुए भी कांग्रेस का राज्य रहा है। लोग तो कहते हैं कि हम दुखी हैं और हम परिवर्तन चाहते हैं लेकिन परिवर्तन लाने वाली जो मशीन है उस मशीन में ही घुन लगा हुआ है, चारों तरफ से लगा हुआ है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक आचार संहिता हम जो राजनीतिक लोग हैं, इनको बनानी चाहिये। नन्दा जी अष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। वे अष्टाचार के उन्मूलन में लगे भी हुए हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में वह भी उतने ही अष्टाचारी हैं जितने और लोग उनकी पार्टी के हैं। वे भी अष्ट हैं जो दूसरों को इस तरह से अष्ट करते हैं। जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं वे इस प्रजातंत्र को खोखला करते जा रहे हैं। उनको इतिहास में क्या कहा जाएगा, समझ में नहीं आता है।

एक माननीय सदस्य : सदाचारी।

श्री काशी राम गुप्त : अगर ऐसे को सदाचारी कहा जाएगा तो दुराचारी कोई और ही होगा।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जयपुर में इनकी पार्टी का अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर एक नाटक बेसा गया था।

वह कहा गया था कि सुखाडिया जी काँग्रेस की ए० आई० सी० सी० के सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने जो ठांचा बनाया था, एकता का जो मलम्मा चढ़ाया था, उसका पर्दाफाश हो गया....

श्री शिव नारायण (बांसी) : श्रीमन् सुखाडिया जी इस हाउस के मੈम्बर नहीं हैं। उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिये। ही शुद्ध नाट भी रेफरेंड।

श्री चंद्रमणि लाल चौधरी (म प्र) : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। वह हमारे एक प्रान्त के मुख्य मंत्री हैं।

श्री धोंकार लाल बेरवा (कोटा) : कौन से रूल के तहत आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा रूल इनफिज हुआ है ?

श्री चंद्रमणि लाल चौधरी : मैं रूल बताता हूँ। आप खामोशी से सुन तो लें।

Mr. Deputy-Speaker: Let not the hon. Member bring in names of persons who are not here to defend themselves.

श्री काशी राम गुप्त : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहाँ पर एक नंगा नाच उसका हुआ और जो लोग वे वे आपस में इस बुरी तरह लड़ने लग गए, इस बुरी तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लग गए कि विदेशी लोग यह समझ गए कि हमारी सोचने की क्या दिशा है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज हमें बहुत पहले करनी चाहिये थी उसको आज भी हम कर लें तो भी अच्छा होगा। अब भी समय है।

Shri Sheo Narain: Tomorrow, you should permit us to take names from the other side also.

Mr. Deputy-Speaker: He should set his own house in order first before referring to others.

श्री काशी राम गुप्त : मैं वह नाम नहीं ले रहा हूँ जिस नाम से किसी व्यक्ति का कोई ज्यादा सम्बन्ध हो। मैं तो सिर्फ विद रेफरेंस टू दै कंटेन्सट बात कर रहा हूँ।

मेरा निवेदन है कि यदि हम सब यह चाहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र की नींव मजबूत हो तो हमको चाहिये कि हम एक प्राचार संहिता बँट कर बनायें, कम से कम एक बात तो हो कि जो धादमी जिस जगह से, जिस टिकट पर चुन कर आया हो, उस धादमी को उस काल के ग्रन्टर दल परिवर्तन करने का अधिकार न हो।

Mr. Deputy-Speaker: All must combine. Then only democracy can be saved.

Shri Kashi Ram Gupta: Democracy can be sustained only when people attach importance to the voters who elected them.

Mr. Deputy-Speaker: Voters know what to do.

श्री काशीराम गुप्त : आज संघर्षों के यहां यह हासत है कि वह इस बात को बहुत बुरा मानते हैं अगर कोई चुनाव के बीच में अपनी पार्टी को छोड़ कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाये, इस लिये किसी की हिम्मत इस तरह की नहीं होती। किन्तु जिस प्रकार से यहां रोजाना अदल-बदल चलता है, सौदेबाजी होती है, वह बहुत ही बातक है और जहाँ तक हो सके इस को हतोत्साहित करना चाहिये। इस लिये एक उपाय हो सकता है, लेकिन पता नहीं आप उसे करना चाहेंगे या नहीं। एक उपाय यह है कि लोक सभा के और विधान सभाओं के जो चुनाव हों वह पुनः-पुनः हों, जिस से दलों के जो प्रांशाम हों वे लोगों को ठीक तरह से समझाये जा

### [श्री काशीराम गुप्त]

सकें। किन्तु यदि यह न किया जा सके तो कम से कम जो चुनाव चिन्हों के गोल माल होते हैं उन को ही रोका जाये। इसके लिये जो भी राजनीतिक दल हों उन के प्रदेशों के चुनाव चिन्ह अलग हों और लोक सभा के चुनाव चिन्ह अलग हों। इस के साथ साथ जो उन के चुनाव घोषणा पत्र होते हैं वह स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेशों के लिये अलग अलग होने चाहियें। अभी हमारे देश में स्थिति यह है कि सारे देश के लिये घोषणा पत्र रखे जाते हैं जब कि चुनाव स्थानीय होते हैं। नतीजा होता है कि चुनाव चिन्हों का गोल माल होता है। आज इस बात को देखते हुए भी कि कांग्रेस को मतदान में 40 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिले, लोक सभा में उस का बहुमत हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग वोट काटने के लिये खड़े होते हैं वह भी एक भ्रष्टाचार की प्रणाली है। उस को समाप्त कर देना चाहिये।

इस के साथ-साथ एक समस्या यह है, हो सकता है कि कांग्रेस के सदस्य इस की हंसी उड़ाये लेकिन उनको भी एक अच्छे विरोधी पक्ष की जरूरत है, कि विरोधी दलों की संख्या किसी प्रकार से कम हो। इस बात को करना बहुत जरूरी होजाता है क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब मैं इस सदन में भ्राया था तब एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब दो हो गई हैं। उस वक्त प्रजा समाजवादी और समाजवादी दल थे। उन्होंने कौने की कोशिश की लेकिन फिर अलग अलग हो गये। यह तो वाम पक्षी दलो बात हुई। जिन को दक्षिण पन्थी कहते हैं उन के बारे में आज कुछ विशेष कहने की प्रावश्यकता नहीं क्योंकि वह अपनी जगह पर मौजूद हैं।

अब मैं कुछ अन्य बिषयों की ओर आता हूँ। सब से पहली बात है भूमि सुधार कानूनों

के बारे में ? इस बारे में शायद श्री शिव नारायण मुन्नासे सहमत होंगे।

श्री शिव नारायण : जरूर, जरूर।

श्री काशी राम गुप्त : जो कानून आज बनते हैं वह जिस ढंग से चलते हैं उस का नतीजा यह होता है कि गरीब किसान मुकदमों में फंसे चले जाते हैं। 100 रु० की जमीन नहीं होती है लेकिन 500 रु० मुकदमें में लग जाते हैं जिसके कारण भूमिहीनों की वह दुर्गंत होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। इधर हम कहते हैं कि फौजियों को जमीनें देंगे, उधर पटवारी फौजियों को धोखा दे कर ऐसी हालत में फंसा देते हैं कि वह मारे-मारे फिरते हैं। फौजी लोग यहां तक गुस्से में आते हैं कि कहते हैं कि हमें जमीन न मिलती तो अच्छा होता। बल्कि एक फौजी हमारे पास आया और कहने लगा कि उसे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि वह पटवारी के ऊपर बन्दूक निकाल दे। मैं ने कहा कि उस पर बन्दूक निकालने से काम नहीं चलेगा। समस्या आज जो हो रही है उस का इलाज करना होगा। आज अगर देखा जाये कि जहां पर जमीन देने का काम हुआ है वहां कितनों को सस्ती जमीन मिली है, और कितने भूमिहीन किसानों को जमीन दी गई है, तो सारी कलाई खुल जायेगी इस बात की। नतीजा यह हुआ है जो भी भूमि सुधार हुआ है उस का फायदा अगर किसी ने उठाया है तो शक्तिवालों ने उठाया है या राजनीतिज्ञों ने उठाया है। ऐसे ऐसे लोगों को जमीनें दी गई हैं जिन्होंने कभी हल में हाथ नहीं लगाया था। जो शहर में रहते हैं या कसबों में रहते हैं उन्हें गांवों में जमीनें भ्रालट कर दी जाती हैं क्योंकि वह सत्ताधारी दल के समर्थक हैं या उन के दल के सदस्य हैं। जब इस तरह की खीचातानी चलती है तब भूमि सुधार का कोई सवाल पैदा नहीं होता। भ्रष्टोत्पादन का सवाल पैदा नहीं होता।

हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभि-  
भाषण में कहा है कि हम गांवों में बिजली  
पहुंचायेंगे। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि  
इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि किस  
बुरी दशा में आज राजस्थान है और किस बुरी  
दशा में आज मध्य प्रदेश है या सारा देश है।  
जहां तक पनबिजली की योजना का प्रश्न है,  
वह फेल हो चुकी है और उन के लिये कह दिया  
जाता है कि पानी नहीं आया। मैं कहना चाहता  
हूँ कि हर पांच साल साल पर ऐसा होता है  
कि पानी नहीं बरसता। यदि चौथी प्लान  
इस तरह की बना दी गई कि बिजली गांवों  
में पहुंचा दी जायेगी और पानी नहीं बरसा तो  
किसान भी तबाह होंगे और उद्योग भी तबाह  
होंगे। आखिर इस बात की जिम्मेदारी किस  
पर डाली जाये ? मैं समझता हूँ कि इस  
की जिम्मेदारी सिवा इस सरकार के  
और किसी के ऊपर नहीं आ सकती है।  
आज जब आपके पास बिजली है ही नहीं तो  
ग्रामों को आप बिजली देंगे कहां से ? इस  
लिये अभिभाषण में जो बातें सरकार लिखती  
है उनका नतीजा यह हो रहा है कि लोग कहते हैं  
कि उनकी करनी और कथनी में रात दिन  
का फर्क है, इस लिये उनका विश्वास मत करो  
और खेती में पैसा न लगाओ।

गोबर गैस का प्लान्ट चलाया गया।  
उस के लिये बार-बार प्रश्न आते रहे। आखिर  
बह फेल ही गया। क्यों फेल हो गया।  
इस का भी प्रश्न इतिहास है। अगर हमारे  
बैज्ञानिक इतने कमजोर हैं कि गोबर की गैस  
इकानामिक नहीं बना सकते या उस  
की खाद इकानामिक नहीं बना सकते तो हम  
किस तरह से आगे चल पायेंगे जिस से कि  
गांवों के अन्दर क्रान्ति आ पाये।

एक माननीय सदस्य : धूप चूल्हे का क्या  
हुआ ?

श्री काशीराम गुप्त : धूप चूल्हे की बात  
छोड़िये। पहले इस चीज के बारे में कह

रहा हूँ। अभी भी नुमायशों में गोबर गैस  
की बात जोर शोर से रखी जाती है। जैपुर  
में कहा गया कि इससे 100 क्यूबिक फीट गैस  
निकलेगी और उसका नतीजा यह निकाला  
जाता है कि लघु उद्योग आगे जायेंगे। मैं बड़े  
बड़े उद्योग धन्धों की बात तो नहीं कह सकता  
क्योंकि वह मजबूती पर बैठ हैं, लेकिन जो छोटे  
उद्योग हैं उन के अन्दर न मालिक खुश हैं  
और न उन में काम करने वाले मजदूर खुश  
हैं। कारण यह है कि जो भी कानून बनाये  
जाते हैं वह बड़े उद्योगों के हित में बनाये जाते  
हैं। छोटे उद्योगों में न तो वह मालिक के  
हित में होते हैं और न मजदूरों के हित में होते  
हैं। यह सरकार कभी भी इस बात की परवाह  
नहीं करती कि छोटे उद्योगों का क्या होने  
वाला है।

अभी-अभी हमारे यहाँ यह हुआ है  
कि सरकार ने कहा कि बिल्डिंग स्टोन का  
काम करने वाले लोगों के लिये प्राविडेंट  
फंड की स्कीम चालू होगी। लेकिन उन  
को नहीं मालूम कि राज्य सरकारें क्या  
करती हैं। वे पांच-पाच बरस के ठेके  
देती हैं। लेकिन आज ठेका किसी के पास है,  
दो तीन वर्ष के बाद वह ठेका किसी और  
के पास होगा क्यों कि बीज का समय  
इतना ही बाकी है। अगर पांच साल के  
लिये प्राविडेंट फंड चालू किया गया तो इन  
मजदूरों को उन से कोई लाभ नहीं होगा  
और वह मारे-मारे फिरेंगे। इस की ओर  
ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हम  
सम्बन्ध में आप को बनना देना चाहता  
हूँ कि अजर मिनरल्स के लिए 20 लाख और  
माइनर मिनरल्स के लिये पांच लाख का लीज  
रखा गया है। अगर हम तरह से 20 लाख  
और पांच लाख की बात को कार्यान्वित कर  
दिया गया तो हम में मजदूरों का क्या  
खतरे में पड़ जायेगा और उन को काफी  
परेशानी होने की सम्भावना है।

### [श्री काशी राम गुप्त]

आज जो कहा जाता है कि हमारी वैज्ञानिक प्रगति होगी, उस के लिये जो योजनाएँ बनाई जाती हैं उन की मूलभूत बातों में यदि हम नहीं जायेंगे और उन को ठीक नहीं करेंगे तो जो हालत आज हमारी योजनाओं की हा रही है उस में बदतर होने वाली है ।

अन्न के उत्पादन के और उस के वितरण के बारे में मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि जब तक आप केवल प्रांकों के प्राधार पर या कागजों के प्राधार पर चलेंगे तब तक आप का काम ठीक से नहीं चल सकता है । अगर अन्न के काम को ठीक करना है तो आप को गांधी के प्राधार पर चलना होगा, एक जिले की जो हालत है उस के प्राधार पर चलना होगा । अभी कुछ दिन हुए डा० के० एल० राव ने एक सुभाव दिया था कि गेहूँ पैदा करने वाले जो जिले हैं उन के लिये भलग-भलग योजना बनाने के बजाय आज भलग-भलग प्रदेशों के लिये योजनाएँ बनती हैं । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो चीज पैदा होती है उसके अनुसार योजना बनाई जाये तो वह ज्यादा ठीक होगा ।

अब प्रश्न आता है खादी कमिशन का । खादी कमिशन जिस योजना को बना कर चल रहा है वह योजना न तो गांधी जी की कल्पना की योजना है न विनोबा जी की और न कांग्रेस की । यह योजना इस तरह से बनाई गई है कि इस से थोड़े से लोगों का भला होता है, जो ऊपर बैठे हुए हैं उन का ही भला होता है । इस से न तो कताई वालों का फायदा होता है और न बुनने वालों का । इसमें प्रामुल चल परिवहन की आवश्यकता है, लेकिन यह काम होने वाला नहीं है क्योंकि उन को यह डर लगता है कि अगर ऐसा कर देंगे तो जो मिल वाले हैं उन की जो प्राधनो आज होती है वह कैसे

होगी इसलिए या तो इसको हमेशा के लिए समाप्त करें या इसको ठीक से चलावें तभी कुछ फायदा हो सकता है अन्यथा आज जो दशा चल रही है वह तो एक खैरातखाना है । थोड़े से लोगों का उससे पेट भर जाता है ।

अब रही शराबबंदी की बात । शराब-बन्दी के बारे में और शिक्षा के बारे में जब तक इस देश की एक नीति नहीं होगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है । आज प्रावाज उठ रही खुद कांग्रेस वालों के अन्दर कि शराबबन्दी उठा दी जाए... (अवधान)...

कई सामाजिक सवस्थ : नहीं नहीं ।

श्री काशी राम गुप्त : मंसूर की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार सभी सरकारें यह मांग कर रही हैं कि इसको हटाओ ।

अब मैं एक खास बात की तरफ उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आँचना चाहता हूँ और वह यह है कि यह जो हिन्दी का प्रश्न है और अँग्रेजी का प्रश्न है इसके भीतर जो राजनीति आ गई है वह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है । या तो सरकार को स्पष्ट कहना चाहिए अगर उनकी हिम्मत नहीं है हिन्दी को चलाने की तो कह दें कि छोड़ो इसको, अँग्रेजी चलाओ और अगर चलानी है तो सबको साथ लेकर उसको चलायें । अभी मैं मद्रास गया । वहाँ हर प्रादमो सोचता है कि हिन्दी वाले हमारे दुश्मन हैं । यह परिस्थिति जहाँ बन जाए वहाँ देश का कल्याण नहीं हो सकता है । इसलिए हिन्दी के सम्बन्ध में सारे देश को एक साथ लेकर एक राउंड कांग्रेस टेबल सरकार को करनी चाहिए और इसको तय करना चाहिए अन्यथा यह प्रश्न देश के टुकड़े करेगा, विभाजन करेगा और हम और गत में चले जायेंगे ।

Shri Karni Singhji (Bikaner): Sir, I want to move any amendment No. 50.

Mr. Deputy-Speaker: It will be taken as moved.

Shri Karni Singhji: I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address no mention has been made—

- (a) about the proposed positive steps to be taken to provide drinking water to the brackish water belt areas in Rajasthan, as for example the Lunkaran-sar area in Bikaner Districts; and
  - (b) about the steps to be taken to arrest the rising price level of essential commodities."
- (50)

Shri Khadilkar: We are grateful to the President for delivering this annual address to both Houses of Parliament because in my view it provides an opportunity to this House to review the national and international situation, our achievements and our failures in the past and see what prospects are before us for the future. As the hon. Members have referred, the greatest achievement to the credit of the government during the last year in my opinion is that when Pakistan committed aggression on a massive scale, we on our side mobilised all the resources and drove the aggressor back. This military victory on the battle front to my mind has resulted in a great moral victory for this country because what has happened at Tashkent is not simply just the signing of a document. It has brought Pakistan and India together, of course after nearly 18 years of strife, Pakistan has been persuaded to accept a course of action which all these years she has spurned. Pakistan has accepted at Tashkent that she is prepared to renounce force for the settlement of disputes. I think it is a moral

victory that was achieved at Tashkent and it will go a long way in bringing about further closer understanding between these two neighbours. During the last eighteen years because of this partition one country was artificially divided into two nations; all the time we were at logger heads. We had a common history, common civilisation, common popular life. In this artificial division of this country some western powers thought it wise to use Pakistan as a lever against India and all the time hatred, mutual suspicion, border disputes and border firing were going on. This House will remember that only after Tashkent during this session we have not heard either of an adjournment motion or a call attention notice or a question regarding some firing on the border. This is due to Tashkent. As my hon. friend from the Opposition just now said, it is an act of faith. I think during the 18 months of the regime of our late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, the events were so crowded; challenges were thrown. There was war; though not declared, it was war none-the-less. Facing the situation, facing every challenge at home and abroad, our late Prime Minister has laid down his life in the hour of glory and triumph by signing the Tashkent agreement; that will change the course of history in the coming years.

Why do I say this? The hon. Member, Shri Dandekar, welcomes the agreement but unfortunately he has not given up his rigid attitude towards those who are instrumental in bringing about India and Pakistan together. Kossygin, by bringing these two countries at war together, and getting this agreement by persuasion, by diplomacy, has achieved one thing. I think in the Soviet diplomatic history this will be recorded as the greatest achievement of Soviet diplomacy. Because, by this act, what has he achieved? Firstly, the leader of the socialist world came forward to settle a dispute between two countries belonging to the Commonwealth and not part of the socialist world.



[Shri Khadiikar]

and more with the west. The western powers, in our eyes during this strife, were suspect. They could not do anything, and the Chinese were taking advantage of this position and trying to win over Pakistan. In such a situation, Soviet diplomacy has triumphed at Tashkent so far as India and Pakistan are concerned. (Interruption).

श्री जयू खड्गिः : प्रौर एक काम किया है । स्वतंत्र प्रौर कम्युनिस्ट पार्टी को एक साथ किया है ।

Shri Khadiikar: वह भी आ जायगा ।

It has brought these countries together, and so far as our borders with China are concerned, though China is still assuming a war posture, the cold war tension or the border tension has been considerably reduced. Not only that, Soviet diplomacy has gone further; excluding South Vietnam, she has entered into an agreement with Japan. The Soviet Union could not see eye to eye as she is not seeing with China, and she has diplomatically, more or less, isolated China, and the only spot of conflict that remains now is Viet Nam. Therefore if we look at Tashkent, Tashkent will be a divide in modern history, a turning-point in world history, if we look at it from the proper angle and try to understand the deep significance of this act of diplomacy that was achieved and an act of crowning glory of our late Prime Minister who achieved it. From this angle I think a great, successful career unfortunately has

been brought to an end in Tashkent. So, Tashkent will always be remembered in history for these two events.

17 hrs.

My hon. friend Shri Dandekar in the same breath, was unfortunately looking at the world events from the same old angle; though he was saying that there is nothing new in the address, if he were to remove his past blinkers from his eyes, he will have a clearer vision. In Vietnam today, the last conflict, strife and war on the Asiatic mainland is being fought; on the Asiatic mainland, Asians are fighting against Asians on the issue, and all over the world democratic opinion is stirred. In America itself, all the intellectuals, all the academicians, all the liberals in sizeable sections of the ruling party are deadly set against this war in South Vietnam. We may be a little weak and poor, but we are a big nation. That big nation image of our country has been developed all over the world by the late Pandit Jawaharlal Nehru. We should not forget it. We should not forget it and act in a cringing manner keeping our mouth shut where we feel, as a matter of principle, we must have our say. Whether our saying has weight or not militarily, certainly we can change this chain of events and restore peace in Vietnam.

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow.

17.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 22, 1966/Phalguna 3, 1887 (Saka).